

# छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में कंवर जनजाति के बच्चों में कुपोषण की समस्या : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

रोशन कुमार

(सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग)  
सी.एम. दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)  
Email - roshankumarkanwar791@gmail.com

**सारांश :** प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में कंवर जनजाति के 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4 एवं NFHS-5), ICDS तथा जिला प्रशासनिक रिपोर्टों के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। NFHS डेटा के अनुसार बिलासपुर जिले में नाटापन 33.7% से घटकर 25.7%, दुबलापन 27.6% से घटकर 24.0% तथा कम वजन 36.8% से घटकर 28.0% हुआ है, जो पोषण कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। इसके विपरीत एनीमिया की दर 51.5% से बढ़कर 78.4% हो गई, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दर्शाती है। ICDS 'वजन त्यौहार' आँकड़ों के अनुसार कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 2021-22 में 17.4%, 2022-23 में 15.2% से घटकर 2023-24 में 13.8% हुआ है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कुपोषण सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य एवं जागरूकता कारकों से प्रभावित है। अतः जनजातीय क्षेत्रों में लक्षित पोषण हस्तक्षेप, बहु-क्षेत्रीय समन्वय एवं सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है। यह शोध पत्र बिलासपुर जिले के कंवर जनजाति के बच्चों में कुपोषण और एनीमिया दूर करने के लिए तथा नीति निर्माण एवं भविष्य के शोध के लिए आधार प्रदान करेगा।

**मूल शब्द :** कुपोषण, कंवर जनजाति, जनजातीय बच्चे, NFHS, ICDS, बाल पोषण, बिलासपुर।

## 1. प्रस्तावना :

कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ की प्रमुख अनुसूचित जनजातियों में से एक है। यह जनजाति मुख्य रूप से राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में निवास करती है। कंवर जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि और वनोपज संग्रह है। कई परिवार छोटेछोटे खेतों पर धान-, कोदोकुटकी तथा अन्य स्थानीय फसलों की खेती करते हैं। इसके अतिरिक्त जंगल से महुआ-, तेंदूपत्ता और लकड़ी जैसी वनोपज भी इनके जीवननिर्वाह का महत्वपूर्ण साधन है- (Anthropological Survey of India, 2013)। कंवर जनजाति की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। इनके पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, त्यौहार और धार्मिक मान्यताएँ प्रकृति तथा स्थानीय देवताओं से जुड़ी होती हैं। सामुदायिक जीवन, पारंपरिक रीति रिवाज और सामाजिक सहयोग इस समुदाय की प्रमुख विशेषताएँ हैं। अन्य कई जनजातीय समुदायों की तरह कंवर जनजाति भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता जैसी चुनौतियों का सामना करती है। ग्रामीण एवं वन क्षेत्रों में रहने के कारण बच्चों में कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच तथा जागरूकता की कमी जैसी समस्याएँ अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती हैं। कंवर जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं (Ministry of Tribal Affairs, 2022)।

कुपोषण भारत में बाल स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर एवं बहु आयामी समस्या है, जिसका प्रभाव विशेष रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था (0-6 वर्ष) में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। पर्याप्त एवं संतुलित आहार के अभाव में बच्चों में शारीरिक वृद्धि बाधित होती है, जिससे अल्पवजन, अवरुद्ध वृद्धि तथा क्षीणता जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं (UNICEF, 2021)। यह स्थिति न केवल बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, बल्कि उनके मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास पर भी

दीर्घ कालीन नकारात्मक प्रभाव डालती है। सरकारी प्रयासों के बावजूद भारत के कई क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या निरंतर बनी हुई है (WHO, 2020)।

जनजातीय समुदाय सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत वंचित माने जाते हैं। इन समुदायों में निवास करने वाले बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता, पोषण संबंधी जानकारी का अभाव, गरीबी, खाद्य असुरक्षा तथा भौगोलिक कठिनाइयों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है (United Nations Children's Fund, 2021)। परिणाम स्वरूप जनजातीय बच्चों में कुपोषण की स्थिति अधिक गंभीर रूप में देखी जाती है (Ministry of Health and Family Welfare, 2021)। छत्तीसगढ़ राज्य, जहाँ जनजातीय जनसंख्या का अनुपात उल्लेखनीय है, वहाँ कंवर जनजाति के बच्चों में कुपोषण एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्या के रूप में उभरती है।

प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में निवासरत कंवर जनजाति के 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस शोध में कुपोषण के स्तर, स्वरूप एवं प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास किया गया है। अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिनमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey), एकीकृत बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services) रिपोर्ट्स के आँकड़े सम्मिलित हैं। उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर कुपोषण की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

बिलासपुर संदर्भ में कंवर जनजाति के बच्चों में कुपोषण की समस्या पर केंद्रित विश्लेषणात्मक अध्ययनों की संख्या सीमित है। इस स्थिति में वर्तमान अध्ययन की आवश्यकता विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह स्थानीय स्तर पर कुपोषण की गंभीरता एवं उससे जुड़े सामाजिक-आर्थिक कारकों को समझने में सहायक होगा। साथ ही, यह अध्ययन जनजातीय बच्चों के पोषण सुधार हेतु प्रभावी नीतियों, कार्यक्रमों एवं समाजकार्य हस्तक्षेपों के विकास में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

## 2. साहित्यिक समीक्षा :

1. UposmaDay एवं Samiran Bisai (2019) ने शोधपत्र "The Prevalence of Under-nutrition among the Tribal Children in India: A Systematic Review" में भारत के जनजातीय बच्चों में कुपोषण की स्थिति का व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस शोधपत्र का अध्ययन करने पर पाया गया कि विभिन्न राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है, कि जनजातीय बच्चों में अल्पवजन, अवरुद्ध वृद्धि एवं क्षीणता की व्यापकता सामान्य आबादी की तुलना में अधिक पाई जाती है। अध्ययन के अनुसार गरीबी, खाद्य असुरक्षा, सीमित स्वास्थ्य सुविधाएँ, मातृ शिक्षा का अभाव तथा भौगोलिक दुर्गमता जैसे कारक कुपोषण के प्रमुख कारण हैं। लेखकों ने यह भी रेखांकित किया है कि वर्तमान पोषण एवं स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ जनजातीय क्षेत्रों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे इस समुदाय के बच्चों में कुपोषण की समस्या बनी हुई है। यह अध्ययन जनजातीय बाल कुपोषण को समझने हेतु एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है।

2. अशोक कुमार डहरिया (2019) ने अपने शोधपत्र "अनुसूचित जाति के बच्चों में कुपोषण की समस्या का विश्लेषणात्मक अध्ययन: छिंदवाड़ा जिला के अमरवाड़ा तहसील के अध्ययन के संदर्भ में" के माध्यम से सामाजिक रूप से वंचित समुदाय के बच्चों में कुपोषण की स्थिति का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति के बच्चों में अल्पवजन, अवरुद्ध वृद्धि एवं पोषण-अभाव की समस्या व्यापक रूप से विद्यमान है, जिसके प्रमुख कारण गरीबी, खाद्य असुरक्षा, मातृ शिक्षा का अभाव, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा सरकारी पोषण योजनाओं का सीमित प्रभाव हैं। लेखक ने क्षेत्रीय स्तर पर कुपोषण की गंभीरता को रेखांकित करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि केवल योजनाओं का अस्तित्व पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन एवं समुदाय-आधारित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह अध्ययन सामाजिक रूप से हाशिये पर स्थित वर्गों में बाल कुपोषण को समझने हेतु एक महत्वपूर्ण शोध-संदर्भ प्रदान करता है।

3. Gajendra Singh, Teeku Sinha एवं Urya Naag (2019) ने अपने अध्ययन "छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी गाँवों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पोषण की स्थिति का अध्ययन" के माध्यम से आदिवासी बहुल बस्तर क्षेत्र में बाल पोषण की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में अल्पवजन, अवरुद्ध वृद्धि एवं पोषण-अभाव की समस्या व्यापक रूप से विद्यमान है। शोध में गरीबी, खाद्य असुरक्षा, मातृ पोषण एवं स्वास्थ्य जागरूकता की कमी, सीमित स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा भौगोलिक दुर्गमता को कुपोषण के प्रमुख कारकों के रूप

में रेखांकित किया गया है। लेखकों ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि पोषण से संबंधित शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन आदिवासी गाँवों में अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है, जिससे लक्षित समुदाय तक योजनाओं का लाभ सीमित रह जाता है। यह अध्ययन जनजातीय क्षेत्रों में बाल कुपोषण की समस्या को समझने हेतु एक महत्वपूर्ण शोध-संदर्भ प्रदान करता है तथा क्षेत्र-विशेष एवं समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों की आवश्यकता को इंगित करता है।

4. Irshad Khan एवं J.K. Nayak (2016) के अध्ययन में "छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के बच्चों की पोषण स्थिति का मूल्यांकन मानवमितीय अध्ययन"। अध्ययन में पाया गया कि 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण की समस्या गंभीर रूप से विद्यमान है, जिसमें कम वजन, अविकसित वृद्धि और क्षीणता के उच्च स्तर पाए गए। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि कुपोषण के प्रमुख कारणों में गरीबी, मातृ कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता, स्वच्छता की कमी तथा पोषण संबंधी जागरूकता का अभाव शामिल हैं। शोध निष्कर्षों के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप लागू करना आवश्यक है।

### 3. अध्ययन के उद्देश्य :

- बिलासपुर जिले में 0 से 6 वर्ष आयु तक के कंवर जनजाति के बच्चों की वर्तमान कुपोषण स्थिति का अध्ययन करना।
- कंवर जनजाति के बच्चों में कुपोषण के विभिन्न स्वरूपों जैसे अल्प वजन, एनीमिया एवं क्षीणता की स्थिति का विश्लेषण करना।
- कंवर जनजाति के बच्चों में कुपोषण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना।

### 4. विधि :

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, द्वितीयक आंकड़ों के संग्रह हेतु संबंधित सरकारी वेबसाइट, शोध पत्रों के माध्यम से तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित किया गया है। इस अध्ययन में कंवर जनजाति के बच्चों में कुपोषण की स्थिति एवं उससे संबंधित कारकों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में मात्रात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिस में उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर कुपोषण की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में कंवर जनजाति के 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की स्थिति को समझने के लिए किया गया है। अध्ययन में केवल द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। इसके लिए जानकारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4 और NFHS-5), आंगनबाड़ी से संबंधित ICDS डेटा, से प्राप्त की गई है। प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित कर के तालिका और प्रतिशत तुलनात्मक माध्यम से विश्लेषण किया गया है, ताकि कंवर जनजाति के बच्चों में कुपोषण की स्थिति और उससे जुड़े कारणों को समझा जा सके। यह अध्ययन उपलब्ध प्रकाशित आँकड़ों पर आधारित है, इस लिए इसके निष्कर्षों को व्यापक स्तर पर लागू करते समय सावधानी रखना आवश्यक है।

### 5. डेटा विश्लेषण (तालिका प्रारूप) :

तालिका 1: बिलासपुर जिले में पोषण संकेतकों का तुलनात्मक विवरण (NFHS)

मानक (Indicators)	NFHS-4 (%) 2015-16	NFHS-5 (%) 2019-21	परिवर्तन (%)
नाटापन	33.7	25.7	-8.0
दुबलापन	27.6	24.0	-3.6
कमवजन	36.8	28.0	-8.8
एनीमिया (6-59 माह )	51.5	78.4	+26.9

तालिका 1 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बिलासपुर जिले में NFHS-4 से NFHS-5 के बीच बच्चों के पोषण संकेतकों में आंशिक सुधार दर्ज किया गया है। नाटापन (33.7% से 25.7%), दुबलापन (27.6% से 24.0%) तथा कम वजन (36.8%

से 28.0%) में कमी दर्ज होना यह दर्शाता है कि बच्चों की समग्र शारीरिक वृद्धि एवं पोषण स्तर में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। यह सुधार पोषण योजनाओं, आंगनबाड़ी सेवाओं तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि एनीमिया की दर में 51.5% से बढ़कर 78.4% होना एक गंभीर चिंता का विषय है, जो यह संकेत करता है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी विशेष रूप से आयरन की कमी अभी भी व्यापक रूप से विद्यमान है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में समग्र पोषण संकेतकों में सुधार के बावजूद एनीमिया नियंत्रण हेतु लक्षित पोषण हस्तक्षेप, पोषण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की सुदृढ़ता की आवश्यकता बनी हुई है। तालिका 2: ICDS 'वजन त्यौहार' के अनुसार बिलासपुर की स्थिति (2021-2024)।

**तालिका 2: बिलासपुर जिले के ICDS डेटा रिपोर्टों के आधार पर**

वर्ष	कुल वजन किए गए बच्चे	कुपोषित बच्चों का प्रतिशत	वार्षिक सुधार दर
2021-2022	1,84,000	17.4%	अधार वर्ष
2022-2023	1,92,000	15.2%	2.2%
2023-2024	1,98,000	13.8%	1.4%

तालिका 2 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 के मध्य कुपोषित बच्चों के प्रतिशत में निरंतर कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 में कुपोषण की दर 17.4 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 15.2 प्रतिशत हो गई, जिसमें 2.2 प्रतिशत का वार्षिक सुधार दर्ज किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में कुपोषण की दर और घटकर 13.8 प्रतिशत हो गई, जिसमें 1.4 प्रतिशत का अतिरिक्त सुधार देखा गया। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि अध्ययन क्षेत्र में बच्चों के पोषण स्तर में क्रमिक सुधार हो रहा है। हालांकि सुधार दर में वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में कमी देखी गई है, जो यह संकेत करती है कि प्रारंभिक वर्षों में योजनाओं का प्रभाव अधिक रहा, जबकि बाद के चरण में सुधार की गति धीमी हुई है। समग्र रूप से यह डेटा पोषण कार्यक्रमों, आंगनबाड़ी सेवाओं तथा स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है, तथापि निरंतर सुधार बनाए रखने हेतु लक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पोषण हस्तक्षेपों की आवश्यकता बनी हुई है।

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में कंवर जनजाति के बच्चों में कुपोषण एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्या के रूप में विद्यमान है, हालांकि उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों के विश्लेषण से हाल के वर्षों में कुपोषण की दर में क्रमिक कमी देखने को मिलती है। NFHS आँकड़ों के अनुसार बौनापन, दुबलापन एवं कम वजन की दरों में कमी यह दर्शाती है कि बच्चों के समग्र पोषण स्तर एवं शारीरिक विकास में सुधार हुआ है। इसी प्रकार वार्षिक आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच कुपोषित बच्चों के प्रतिशत में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है, जो पोषण योजनाओं, आंगनबाड़ी सेवाओं एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

इसके बावजूद एनीमिया की उच्च दर यह संकेत करती है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी विशेष रूप से आयरन की कमी अभी भी गंभीर समस्या बनी हुई है। सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, सीमित स्वास्थ्य सुविधाएँ, मातृ शिक्षा का निम्न स्तर, पोषण संबंधी जागरूकता की कमी तथा पारंपरिक आहार पद्धतियाँ कुपोषण की समस्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक पाए गए हैं। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि शासकीय योजनाएँ संचालित होने के बावजूद जनजातीय क्षेत्रों में उनका प्रभाव अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पा रहा है। अतः केवल योजनाओं का संचालन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, सामुदायिक सहभागिता एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पोषण रणनीतियों की आवश्यकता है।

## 6. निष्कर्ष एवं सुझाव :

इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कंवर जनजाति के बच्चों में कुपोषण की समस्या अभी भी एक महत्वपूर्ण जनस्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, यद्यपि उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों के अनुसार कुपोषण प्रतिशत में पिछले कुछ वर्षों में क्रमिक कमी देखी गई है। NFHS-4 और NFHS-5 के तुलनात्मक विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि नाटापन, दुबलापन एवं कम वजन के मामलों में कमी आई है, जो सरकारी पोषण कार्यक्रमों, आंगनबाड़ी सेवाओं तथा सामुदायिक पोषण जागरूकता गतिविधियों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि, एनीमिया की दर में वृद्धि यह संकेत देती है कि सूक्ष्म पोषक

तत्वों की कमी अभी भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, वजन त्यौहार जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से कुपोषित बच्चों की पहचान एवं निगरानी में सुधार हुआ है, जिससे वार्षिक सुधार दर में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि कुपोषण केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं जागरूकता से जुड़े कारकों से भी प्रभावित होती है।

जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण नियंत्रण हेतु बहु-क्षेत्रीय समन्वित रणनीति को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य विभाग एवं पोषण पुनर्वास केंद्रों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर नियमित वृद्धि निगरानी को प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है। गर्भवती एवं धात्री माताओं के पोषण, स्तनपान प्रथाओं तथा पूरक आहार से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों को सामुदायिक स्तर पर सुदृढ़ किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पोषक खाद्य पदार्थों को पोषण योजनाओं में शामिल कर खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही, वजन त्यौहार जैसे कार्यक्रमों को वैज्ञानिक एवं नियमित तरीके से लागू कर जोखिम वाले बच्चों की समय पर पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ सामुदायिक सहभागिता, पोषण शिक्षा, तथा डेटा आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है, जिससे कुपोषण दर में दीर्घकालिक एवं सतत सुधार लाया जा सके।

### संदर्भ सूची :

1. Day, U., & Bisai, S. (2019). The prevalence of under-nutrition among the tribal children in India: A systematic review. *Journal of Public Health Research & Development*, 10(6), 178–184.
2. Dahariya, A. K. (2019). अनुसूचित जाति के बच्चों में कुपोषण की समस्या का विश्लेषणात्मक अध्ययन: छिंदवाड़ा जिला के अमरवाड़ा तहसील के अध्ययन के संदर्भ में. *International Journals of Hindi Research*, July 2019.
3. Singh, G., Sinha, T., & Naag, U. (2019, October 28). छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी गाँवों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पोषण की स्थिति का अध्ययन. *HSSOA Journal of Internal medicine And Primary health care*.
4. Khan, I., & Nayak, J. K. (2018). Nutritional status of Hill Korwa children in Sarguja district, Chhattisgarh: An assessment through Z-score analysis. *International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, 5(3).
5. Women and Child Development Department, Government of Chhattisgarh. (2024). District Nutrition and ICDS Progress Report: Bilaspur District (2021–2024). Raipur: Government of Chhattisgarh.
6. Bilaspur District Administration. (2024). Annual Progress Report: Child Nutrition Status and Anganwadi Monitoring Data (2021–2024). Bilaspur: Government of Chhattisgarh.
7. International Institute for Population Sciences (IIPS), & ICF. (2017). National Family Health Survey (NFHS-4), 2015–16: India. Mumbai: IIPS.
8. International Institute for Population Sciences (IIPS), & ICF. (2021). National Family Health Survey (NFHS-5), 2019–21: India. Mumbai: IIPS.
9. Ministry of Tribal Affairs. (2022). *Annual report 2021–22*. Government of India. New Delhi.
10. Anthropological Survey of India. (n.d.). *Tribal communities of India*. Government of India. Retrieved from <https://ansi.gov.in>